शहरी सस्ते में पाएंगे बिजली, केंद्र व राज्य सरकारों की सब्सिडी अब कुल 60 फीसदी हो जाएगी

सोलर बिजली के लिए सरकार देगी 30% सब्सिडी

अच्छी खबर

लखनऊ | पंकज सिंह

शहर में अगर आपके घर की छत पर जगह है तो सोलर रूफ टॉप प्लांट लगाने से आपका बिजली बिल कम हो सकता है। वहीं गांव में बिना बिजली के हैं तो यह संकट भी सस्ते सोलर प्लांट से दूर हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने सोलर प्लांट पर 30 फीसदी तक सब्सिडी देने जा रही है। यह केंद्र सरकार से मिलने वाली 30 फीसदी की छूट से अलग होगी। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सोलर पॉवर सेक्टर में जबरदस्त उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। प्राइवेट कंपनियों के लिए भी यूपी एक बड़े बाजार के तौर पर उभर रहा है।

प्रदेश सरकार इस सब्सिडी के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ला रही है। इसके लिए सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। आचार संहिता के बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी।

> 25 वर्ष तक खर्च नहीं पेज 10

जेब पर बोझ नहीं

- सब्सिडी देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी
- लागू होने के बाद सोलर पावर के क्षेत्र में उछाल की उम्मीद

पांच किलोवाट का प्लांट लगाने में खर्च होंगे 1.40 लाख

अभी रूफ टॉप सोलर प्लांट की औसत लागत 70 हजार रुपये प्रति किलोवाट तक आती है। पांच किलोवाट के प्लांट लगाने पर करीब 3.5 लाख रुपये खर्च होते हैं। इसमें 30 फीसदी (करीब 1.05 लाख रुपये) केंद्रीय सब्सिडी मिल जाती है। फिर भी उपभोक्ता को 2.45 लाख रुपये निवेश करना पड़ता है। जो काफी महंगा पड़ता है। अब प्रदेश सरकार भी 30 फीसदी सब्सिडी देगी। इससे कीमतें घट कर महज 1.40 लाख रुपये रह जाएगी।

प्लांट लगाने पर 25 साल तक खर्च नहीं

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

एक बार प्लांट लगने के बाद साफ-सफाई के अलावा बहुत अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। पांच सालों तक इसकी मरम्मत और रिपेयर की जिम्मेदारी प्लांट लगाने वाली कंपनी या यूपी नेडा संभालती है। शहरी उपभोक्ता अपनी छतों पर लगे प्लांट से जितनी बिजली का उत्पादन करेंगे वह सीधे ग्रिड में चली जाएगी। उपभोक्ता ग्रिड से जितनी बिजली लेगा उतनी यूनिट कम कर बाकी का नगद भुगतान कर दिया जाएगा। इससे एक तरह से फ्री बिजली मिल सकेगी। गांव में प्लांट लगाने वाले के घर में बिजली आएगी, वहां मोबाइल टॉवर या अन्य घरों में बिजली देकर अतिरिक्त आय कर सकेंगे।

केंद्र की रूफ टॉप सोलर योजना से भी कमाई: केंद्र सरकार इस योजना के तहत मकान मालिकों से समझौता कर उनके घरों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाएगी। पांच से 10 किलोवाट क्षमता के ये सोलर प्लांट से 15 से 30 हजार यूनिट प्रतिमाह तक बिजली पैदा होगी। यह बिजली सीधे ग्रिड पर ले ली जाएगी। यूनिट के अनुसार तय रेट से भवन स्वामी को भुगतान मिलेगा। प्लांट की क्षमता और बिजली यूनिट के उत्पादन के अनुसार यह 30 हजार से 50 हजार रुपये प्रति माह तक हो सकता है।

सोलर पॉवर पॉलिसी लागू की गई है। इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष छूट दिए जाने पर विचार हो रहा है। इससे गांवों में लोगों तक बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी ही शहरी लोगों पर बिजली बिल का बोझ भी कम होगा। साथ ही बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा।

आलोक कुमार, प्रमुख सचिव ऊर्जा